[Shri Indrajit Gupta]

ing level of credit facilities, to prosper or not. That is not my test, but that is the test which the private sector applies to itself.

I do not find any available evidence for this contention that credit facilities are inadequate or that credit supplies are drying up to such an extent that the development of industry, particularly in the private sector, is not able to earn an adequate return on its capital. Profitability is the law of the private sector. That must be the yardstick by which we have to test. I will come to that presently, but one other point I would like to make first, in passing, namely that the Mahalanobis Committee's Report has not yet been released to the public. It has been submitted to the Government and in the usual way in our democratic set-up—I do not know how—huge passages of it seem to have leaked out to the press.

An Hon. Member: It was placed on the Table yesterday.

Shri Indrajit Gupta: I am very sorry; I was absent from the House for a long time, but anyway that is good.

I am surprised to find that this Bill is being brought forward just at the moment when the Mahalanobis Committee has observed in its report that one of the causes, not the only one or the main one but one of the principal causes, which have contributed to the development of economic concentration and the growth of monopoly in our method of planed economy is the way in which the existing financial institutions have functioned.

This observation of the Mahalanobis Committee may not be acceptable to the Government. Government may contest it. Government may come forward with its own arguments and facts and figures to prove that this is wrong. But the Mahalanobis Committee has laboured long and I believe that its report and its recommendations and observations do deserve most serious consideration by the Government. It is really strange that just at the time when this Committee's report has seen the light of the day and when they have stated that loans advanced by public institutions, like, the Industrial Finance Coroporation and the National Industrial Development Corporation have aided the growth of the private sector in industry and specially big companies and their growth have been facilitated by the financial assistance rendered to them by these institutions, they have observed that there can be no doubt that the working of our planned economy—and they have referred here specifically to the working of these financial institutions—has encouraged the process of concentration by facilitating and aiding the growth of big business in India.

Mr. Speaker: Would he like to take more time?

Shri Indrajit Gupta: I do not know how much time is allotted. .....

Mr. Speaker: I did not want to interrupt him or to stop him. He might resume his seat.

13.23 hrs.

RE: RECEPTION TO SHEIKH ABDULLAH

Mr. Speaker: Mr. Prakash Vir Shastri and other Members had given a Calling Attention Notice this morning about Mr. Dinesh Singh's going and receiving Sheikh Abdullah. I have not allowed that.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): And also the Commonwealth Secretary, Mr. C. S. Jha.

Mr. Speaker: I have rejected that. But then he wanted to interrupt the proceedings and he raised that question. The Prime Minister is here. If he wants to make a statement, he might do it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Is he making a statement *suo motu*?

Mr. Speaker: I had rejected that. He is making it *suo motu*.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ग्राप ने कहा था कि हम इस सम्बन्ध में शार्ट-नोटिस क्वेस्चन पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर वैसे ही भारी बात सामने ग्रा जाये, तो उन की क्या जरूरत है।

प्रधान मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा ग्रणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दोनों साहब जो गये थे, वे मेरे खास कहने पर मेरे उन से खास दरख्वास्त करने पर, गये थे, कि वे वहां जायें। एक तो कर्टसी की बात थी ग्रौर दूसरे इन्तजाम देखने के लिए कि वहां पर इन्तजाम ठीक है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्राज पहले भी यह निवेदन किया था कि शेख ग्रब्दुल्ला किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि नहीं हैं। वह भारतवर्ष के ही एक सामान्य ग्रादमी हैं, जिस तरह कि दूसरे ग्रौर व्यक्ति हैं। राजा दिनेश सिंह व्यक्तिगत स्थिति में नहीं गये, क्योंकि वह उप-विदेश मंत्री हैं ग्रौर उन पर देश की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसी तरह से एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी, श्री झा, भी शेख ग्रब्दुल्ला को लेने के लिए वहां गए। जब कभी सदरे-रियासत या सादिक साहब दिल्ली में ग्राए, तो उन को लेने के लिए उप-विदेश मंत्री कभी नहीं गए। तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए उन के जाने की क्या जरूरत थी, जिस के मुकद्दमे का भी ग्रभी फैसला नहीं हुग्रा है ग्रौर जेल से निकलते ही जिस ने इस तरह के बयान दिये हैं, जो कि हिन्दुस्तान के गौरव ग्रौर प्रतिष्ठा के सरासर विपरीत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या यह हर एक भारतीय के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सवाल कर लिया। बाकी बातें रेलिवेंट नहीं हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बारे में ग्रौर कुछ कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि जब काश्मीर के सदरे रियासत या चीफ मिनिस्टर ग्राते हैं, तो कभी कोई उन को लेने के लिए नहीं जाता है। उनका कहना है कि चूंकि वे शेख ग्रब्दुल्ला को खास तौर पर लेने के लिए गए, इस लिए क्या इस से यह न समझा जाएगा कि वह किसी दूसरे मुल्क से ग्रा रहे हैं। उनका कहना है कि हम ग्रपनी कन्डक्ट से ऐसा जाहिर कर रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जाहिर है कि दूसरा मुल्क नहीं है। लेकिन बारह बरस के बाद वह यहां ग्राए। बीच में बहुत बातें हुई। करीब ग्यारह बरस वह जेल में रहे। सब वाकयात हुए। इसलिए उन के ग्राने पर खास तौर से इन्तजाम की जरूरत थी। चुनाचे दोनों साहबों को कहा गया कि जाग्रो, देख लो, वहां इन्तजाम ठीक है या नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर। मेरे कहने का ग्रभिप्राय यह है कि राजा दिनेश सिंह ग्रौर एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की ग्रपनी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है। क्या वे सिर्फ शेख ग्रब्दुल्ला के लिए ही इन्तजाम देखने के लिए गए या ग्रब तक जितने भी लोग ग्राते रहे हैं, उन सब के लिए इन्तजाम देखने के लिए वे इस तरह से जाते रहे हैं ? यह एक ऐसी स्थिति है, जिससे सारे देश में चिंता पैदा हो गई है। सामान्य रूप से इन्दिरा जी, मसानी साहब कोई भी जाते, कोई ग्राबजेक्शन नहीं था। वह उन के घर पर मेहमान थे। लेकिन उप विदेश मंत्री ग्रौर एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को क्यों भेजा गया, ग्रापत्ति तो यह है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने इन दोनों से कहा जाने के लिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्यों कहा जाने के लिए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने मुनासिब समझा । (*Interruptions.*)

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : क्यों मुनासिब समझा ? क्या ऐसे व्यक्ति का इस तरह स्वागत करना मुनासिब है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । एक सवाल किया गया है । प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब दे रहे हैं । माननीय सदस्य जवाब के बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उनका जाना मुनासिब समझा, इसलिए मैं ने उन से कहा । मैं इस सब बहस में तो पड़ा नहीं था, जो कि माननीय सदस्य ने बयान की है । मैंने] मुनासिब समझा कि वे जायें और उन का इस्तकबाल करें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के दिल में यह खदशा है कि दूसरे लोग इस बारे में गवर्नमेंट के इरादे का कुछ मुख्तलिफ इन्टरप्रटेशन कर सकते हैं । उन का कहना है कि लोग इससे समझ सकते हैं कि इस बारे में कोई खास चीज की गई ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि आप ने कहा है इसमें कोई खास चीज नहीं थी । वह मेरे मेहमान थे । मैंने अपनी मिनिस्ट्री के इन दोनों साहबों को कहा कि जाकर देख लीजिए । (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें बहुत सवालों की गुंजायश नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रधान मंत्री जी बार बार कह रहे है कि "मैंने मुनासिब समझा"। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने, या प्रधान मंत्री ने भी यह मुनासिब समझा ? प्रधान मंत्री देश के गौरव के रक्षक हैं। वह एक व्यक्ति नहीं हैं। जब वह यह कहते हैं कि "मैंने मुनासिब समझा", तो क्या उन्होंने व्यक्तिगत स्थिति में मुनासिब समझा या एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुनासिब समझा ? अगर उन्होंने प्रधान मंत्री की दृष्टि से मुनासिब समझा, तो क्यों, यह सवाल है, जिसे हम उनसे पूछना चाहते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : ये सब रंजीदा सवाल तो मेरे सामने नहीं थे कि मैं किस हैसियत से कह रहा हूं । लेकिन यह कहना सही हो सकता है कि मैंने प्रधान मंत्री की हैसियत से भी कहा था दोनों साहबों को जाने के लिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : तो गलत किया है—देश के साथ अन्याय किया है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, इन्तजाम देखने का काम या तो पुलिस का है, या इन्टैलिजेंस ब्यूरो का है या वाच एंड वार्ड का है । हमारे उप विदेश मंत्री का वह काम नहीं है, जो कि उन्हें सौंपा गया । यह गलत सुपुर्दगी कैसे कर दी गई ?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा कि वह हमारे मेहमान और मेहमान नवाजी या जर्रा नवाजी करना हमारा धर्म है । इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेख साहब की काफी हिम्मत अफजाई होगी और हिन्दुस्तान का जो कहना है, हमारा जो कहना है काश्मीर के बारे में उसके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई हो कि कुछ चीज उनकी भी मान ली जाएगी ? क्या प्रधान मंत्री—

अध्यक्ष महोदय : उनके मन की दशा का उन पर क्या असर हुआ, यह प्रधान मंत्री कैसे जवाब दें. . . .

Shri S. M. Banerjee: Whether this has given an encouragement......

Mr. Speaker: Who can say that?

सवाल यह आप करते हैं कि उनके दिमाग की दशा इस बात में क्या हुई—

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा कि चाहे जानी या प्रधान मंत्री की हैसियत से कहा है और ये जो पेचीदा बातें हैं, ये उनके दिमाग में नहीं थीं। वहां पर सिक्योरिटी का सारा इंतजाम होते हुए स्पेशल प्रोटोकाल का इंतजाम किया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दिमाग में ऐसी कोई बात आ गई हो जिससे उनकी हिम्मत अफजाई हो गई हो ? क्या प्रधान मंत्री जी विश्वास दिलायेंगे. . .

Mr. Speaker: Shri Kapur Singh.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): The question that is worrying us all and that is worrying many people inside and outside the House is precisely this. Were the representative of the Ministry of External Affairs and the Secretary in-charge of the Commonwealth Relations specifically picked up for receiving Sheikh Abdullah or was it something fortuitous? That is the only question.

Shri Jawaharlal Nehru: Those gentlemen were especially asked by me to go there simply because ....

Mr. Speaker: His question is: Was this selection made because one was the Deputy Minister in the Ministry of External Affairs and the other was the Secretary in-charge of Commonwealth Relations? Were they in that capacity particularly selected to receive Sheikh Abdullah?

Shri Jawaharlal Nehru: I do not understand all these questions. All these matters were not considered from that point of view by me or by anybody else.

Mr. Speaker: When a citizen of India is coming here, there ought not to be such respect of distinction shown to him that the Deputy Minister in the Ministry of External Affairs should go there. What I can gathei from their questions is, that is what is worrying them

Shri Jawaharlal Nehru: I do not think they need be worried about that because the Deputy Minister went at my request and the Commonwealth Secretary went at my request largely because I had to deal with them and they were roundabout me.

Mr. Speaker: Because they wer roundabout him, they were his own assistants or subordinates, whatever they were, Prime Minister says, he sent them there. That should be all. I do not think there is anything more.

Shri Kapur Singh: Selection was merely fortuitous.

Mr. Speaker: That is all.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ——

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं पूछ सकते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : बड़े महत्व का सवाल है। मैं पहले भी खड़ा हुआ था । यह ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई महत्व न दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया था कि स्वागत करने के लिए नहीं जाना है ।

ऐसा कहने के बाद भी उसके दिमाग को खराब करने के लिए स्वागत करने के लिए गए तो इसका क्या कारण था ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जेल से छोड़ने की जितनी बड़ी गलती की, उसी तरह की यह दूसरी गलती है कि उसके दिमाग को खराब किया जा रहा है ——

अध्यक्ष महोदय : ब्यान आपने सुन लिया है और सवाल भी पूछ लिये है । और अब अगर कुछ चाहते हैं तो वह यहां इस वक्त नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उत्तर स्पष्ट तथा संतोषजनक मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

13.31 hrs.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA BILL—*contd.*

Shri Indrajit Gupta· Before this unfortunate interlude took place, I was making the point that Government would have been beter advised, and it would have been more graceful on the part of the Finance Minister to have deferred the bringing forward of this Bill before this House for its consideration, until Government had had sufficient time and opportunity to go into the Mahalanobis Committee's report which has made an observation on this precise point regarding the functioning of financial and credit institutions in our economy and has made a very alarming observation to the effect that the manner in which they have operated has been one of the main contributory factors responsible for the growth of monopoly and economic concentration. This Bill is seeking to provide yet another institution, which in fact will be a much bigger and a much more centralised and powerful financial institution than any of those existing at the moment. I think that this kind of attitude on the part of Government does smack a little of prejudging their ultimate decisions on the Mahalanobis Committee's report, and it also shows or betrays a certain attitude of contempt, if I may say so. For, what is the point in setting up a committee and allowing it to work for so long and then produce a report, at the same time not giving sufficient consideration to one of the most vital points emphasised by that committee, before bringing forward a Bill which will add to the multiplicity of those very financial institutions whose functioning the Mahalanobis Committee has criticised?

As I was saying earlier, apart from seeing a total overall gap, which is always bound to be there in my view between the total requirements of economic or industrial development on the one hand, and the available credit facilities given by the existing institutions on the other, what evidence is there to show that the private sector industrial development is being hampered or being hamstrung or being handicapped by shortage of credit to such an extent that its profitability rate or the return that it can earn on its capital investment is not satisfactory? I do not find it anywhere.

As a matter of fact, since we are now passing through a phase, when as the Finance Minister has recently emphasised many times, there is the need for the country to go ahead more boldly on the question of foreign collaboration and joint ventures, obviously, any bank of this kind which is proposed to be set up must have as one of its important functions the question of providing credit and financing such joint ventures also.

Only a day or two ago, I found these figures which are just an illustrative example. The Indian Investment Centre publishes a news leter. The latest one for the month of April gives some interesting facts which are quite illustrative. They say that in the month of March, the Government of India have approved of 38 collaboration projects of which 13 are completely new projects, and in those projects, the total investment will amount to Rs. 6.78 crores, and out of that Rs. 6.78 crores, the foreign share will be Rs. 1.48 crores; that means that the domestic share will be Rs. 5.30 crores.